

India and Yemen have also agreed on the need for greater cooperation between the two countries to strengthen the Non-aligned Movement and the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC).

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गए मामले

2707. श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत सात माह के दौरान सभी राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजे गए उन मामलों का ब्यौर क्या है जो गत तीन वर्षों के लम्बित पड़े थे;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौर क्या है और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कुल कितने मामले प्रेषित किए गए हैं; और

(घ) लम्बित पड़े मामलों को कब तक सुलझा लिए जाने की सम्भावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पिछले सात माह के दौरान, राज्य सरकारों द्वारा उक्त ब्यूरो को दो मामले भेजे गये थे जो पिछले तीन साल से अनिर्णीत (लम्बित) चल रहे हैं। इन दो मामलों में से एक मामला गाजियाबाद के निवासी राज हंस पाल का कुछ अज्ञात शररती व्यक्तियों द्वारा दिनांक 14.02.96 को किए गए अपहरण के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया है, यह ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच के अधीन है तथा इस पर आधारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आराधना श्रीवास्तव की हत्या के बारे में बिहार सरकार द्वारा भेजा गया मामला केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा हाथ में नहीं लिया गया है क्योंकि राज्य पुलिस द्वारा इस मामले में पहले ही आरोप-पत्र दायर कर दिया गया है।

Home posting of re-employed ex-servicemen

2708. SHRI LAJPAT RAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether ex-servicemen re-employed in Union Government jobs

after retirement are given any special opportunity to post them in Home States;

(b) if not, whether, keeping in view various difficulties being faced by them, Government propose to issue guidelines for their Home transfers;

(c) whether Government have received any representations in this context from Punjab; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) and (b) After their discharge/retirement from Armed Forces, ex-servicemen are employed in Civilian Departments/ Offices as well as in Central Para Military Forces. Director General Resettlement and District Sainik Boards, extend necessary help to the ex-servicemen in securing jobs as per options of the ex-servicemen. After their appointment, they are treated at par with other employees of the organisation in which they are employed. There is no proposal to issue any guidelines regarding their posting as the same may not be in public interest.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Advertisement of posts to be filled on deputation

2709. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that posts to be filled on deputation are to be circulated to all the Government departments and simultaneously advertised in the Employment News;

(b) if so, the details thereof and the reasons for the same not being followed in filling up the posts of General Managers, Managing Directors in the